भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 5677

जिसका उत्तर शुक्रवार, 04 अप्रैल, 2025 को दिया जाना है

उच्च न्यायपालिका और न्यायाधिकरणों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के न्यायाधीशों की संख्या

5677. श्रीमती कनिमोझी करुणानिधि :

क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अधीनस्थ न्यायालयों, विशेषकर जिला न्यायालयों में सेवारत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के व्यक्तियों की राज्यवार संख्या कितनी है ;

(ख) क्या सरकार के पास विभिन्न विधियों के तहत गठित केंद्रीय और राज्य न्यायाधिकरणों में सेवारत उक्त समुदायों के न्यायिक अधिकारियों के संबंध में आंकड़े हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) पिछले दस वर्षों के दौरान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के न्यायाधीशों या न्यायिक अधिकारियों की नियुक्तियों का राज्यवार ब्यौरा क्या है ; और

(घ) क्या उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया में आरक्षण मानदंडों का पालन किया जाता है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(**क**) : न्याय विभाग के एमआईएस (प्रबंध सूचना प्रणाली) पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार तारीख 02.04.2025 तक अधीनस्थ न्यायालयों**,** विशेष रूप से जिला न्यायालयों में सेवारत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों से न्यायिक अधिकारियों की राज्यवार संख्या उपाबंध-1 पर है ।

(ख) : विभिन्न परिनियमों के अधीन गठित केन्द्रीय और राज्य अधिकरणों में सेवारत उक्त समुदायों से न्यायिक अधिकारियों की संख्या केन्द्रीय रूप से नहीं रखी जाती है ।

(ग) और (घ) : पिछले दस वर्षों के दौरान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों से न्यायाधीशों या न्यायिक अधिकारियों की नियुक्तियों के राज्यवार ब्यौरे विभाग में उपलब्ध नहीं हैं तथापि, एमआईएस पोर्टल पर उपलबध जानकारी के अनुसार, गत पांच वर्षों के दौरान जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों से न्यायिक अधिकारियों की कार्यरत पद संख्या उपाबंध-2 पर है ।

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 217 और अनुच्छेद 224 के अधीन की जाती है, जो किसी जाति या वर्ग के व्यक्तियों के लिए आरक्षण का उपबंध नहीं करते हैं । अत:, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों में एससी, एसटी और ओबीसी के प्रतिनिधित्व से संबंधित प्रवर्ग वार आंकड़े केन्द्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं ।

तथापि, वर्ष 2018 से, उच्च न्यायालय न्यायाधीशों के पदों के लिए सिफारिश किए गए व्यक्तियों से अपेक्षा की जाती है कि वे विहित रूप विधान (उच्चतम न्यायालय से परामर्श करके तैयार किया गया) ने अपनी सामाजिक पृष्ठभूमि के बारे में ब्यौरे उपलबध कराए । तदनुसार, सिफारिश किए गए व्यक्तियों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, वर्ष 2018 से नियुक्त किए गए 719 उच्च न्यायालय न्यायाधीशों में से, 22 न्यायाधीश अनुसूचित जाति प्रवर्ग के थे, जबकि 16 न्यायाधीश अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग के थे ।

प्रक्रिया ज्ञापन (एमओपी) के अनुसार, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रस्तावों की पहल करने का उत्तरदायित्व भारत के मुख्य न्यायमूर्ति में निहित होता है, जबकि उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रस्तावों की पहल का उत्तरदायित्व संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति में निहित होता है । तथापि, सरकार, उच्च नयायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों से अनुरोध करती रही है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव भेजते समय, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्संख्यक वर्गों या महिलाओं के उपयुक्त अभ्यर्थियों का उचित ध्यान रखा जाए जिससे उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति में सामाजिक असमानता सुनिश्चित की जा सके । केवल वे व्यक्ति ही जिनकी उच्चतम न्यायालय कोलेजियम द्वारा सिफारिश की जाती है, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त किए जाते हैं ।

जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में नियुक्तियां, भारत के संविधान के अनुच्छेद 233 और अनुच्छेद 234 के अनुसार राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आती हैं । भर्ती प्रक्रिया उच्च न्यायालयों के परामर्श से राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार शासित की जाती है ।

******

उपाबंध-1

"उच्चतर न्यायपालिका और अधिकरणों में एससी/एसटी न्यायाधीशों की संख्या" के बारे में लोकसभा अतारांकित प्रश्न सं. 5677 जिसका उत्तर तारीख 04.04.2025 को दिया जाना है, के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।

02.04.2025 **तक जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में एस सी/एसटी न्यायिक अधिकारियों की कार्यरत पद संख्या**

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	सिविल न्यायाधीश(जूनियर डिविजन)		सिविल न्यायाधीश (सीनियर डिविजन)		जिला न्यायाधीश/डी.जे.	
		एससी	एसटी	एससी	एसटी	एससी	एसटी
1	अंदमान और निकोबार	0	0	0	0	0	0
2	आंध्र प्रदेश	53	19	23	10	30	3
3	अरुणाचल प्रदेश	0	9	0	16	0	7
4	असम	16	23	12	21	6	7
5	बिहार	129	9	63	5	48	3
6	चंडीगढ़	7	0	0	0	1	0
7	छत्तीसगढ	26	57	17	45	30	26
8	दादरा और नागर हवेली	0	0	0	0	0	0
9	दमण और दीव	0	0	0	0	0	0
10	दिल्ली	46	21	12	1	10	1
11	गोवा	0	2	0	0	0	0
12	गुजरात	59	1	50	4	8	0
13	हरियाणा	31	0	42	0	21	0
14	हिमाचल प्रदेश	8	2	8	4	6	1
15	जम्मू - कश्मीर	13	11	6	7	9	7
16	झारखंड	15	31	0	0	0	0
17	कर्नाटक	77	19	90	20	60	9
18	केरल	20	0	11	1	11	1
19	लद्दाख	1	2	0	4	0	1
20	लक्षदीप	1	0	0	1	0	0
21	मध्य प्रदेश	122	55	62	90	85	92
22	महाराष्ट्र	140	2	43	3	44	2
23	मणिपुर	0	6	0	4	0	4
24	मेघालय	0	15	0	21	0	18
25	मिजोरम	0	13	0	17	0	15
26	नागालैंड	0	0	0	0	0	0
27	ओडिशा	30	4	0	0	0	0
28	पुडुचेरी	3	0	0	0	0	0
29	पंजाब	118	0	34	0	33	0
30	राजस्थान	64	47	60	52	59	24
31	सिक्किम	0	1	0	2	0	5
32	तमिलनाडु	119	5	57	4	35	1
33	तेलंगाना	38	20	15	7	15	13
34	त्रिपुरा	5	9	4	7	4	6
35	उत्तर प्रदेश	214	17	134	15	191	7
36	उत्तराखंड	16	3	12	4	18	5
37	पश्चिमी बंगाल	0	0	0	0	0	0
कुल		**1371**	**403**	**755**	**365**	**724**	**258**

स्रोत: न्याय विभाग का एमआईएस पोर्टल।

उपाबंध-2

"उच्चतर न्यायपालिका और अधिकरणों में एस सी/एसटी न्यायाधीशों की संख्या" के बारे में लोकसभा अतारांकित प्रश्न सं. 5677 जिसका उत्तर तारीख 04.04.2025 को दिया जाना है, के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।

31.12.2020 **तक जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में एससी/एसटी न्यायिक अधिकारियों की कार्यरत पद संख्या**

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	सिविल न्यायाधीश(जूनियर डिविजन)		सिविल न्यायाधीश (सीनियर डिविजन)		जिला न्यायाधीश/डी.जे.	
		एससी	एसटी	एससी	एसटी	एससी	एसटी
1	अंदमान और निकोबार	0	0	0	0	0	0
2	आंध्र प्रदेश	43	16	29	8	16	1
3	अरुणाचल प्रदेश	0	13	0	9	0	9
4	असम	12	18	10	18	0	0
5	बिहार	123	10	77	4	20	1
6	चंडीगढ़	2	0	0	0	0	0
7	छत्तीसगढ	20	48	18	29	22	27
8	दादरा और नागर हवेली	0	0	0	0	0	0
9	दमण और दीव	0	0	0	0	0	0
10	दिल्ली	53	5	1	1	7	1
11	गोवा	0	2	0	0	0	0
12	गुजरात	58	2	46	3	11	1
13	हरियाणा	39	0	25	0	22	0
14	हिमाचल प्रदेश	10	5	7	1	6	2
15	जम्मू -कश्मीर	9	6	10	4	5	6
16	झारखंड	26	62	0	0	0	0
17	कर्नाटक	76	14	48	9	44	7
18	केरल	22	1	5	0	7	0
19	लद्दाख	0	4	0	1	0	0
20	लक्षदीप	1	0	0	1	0	0
21	मध्य प्रदेश	106	94	71	87	63	54
22	महाराष्ट्र	140	2	43	3	44	2
23	मणिपुर	0	2	2	4	0	5
24	मेघालय	0	20	0	14	0	12
25	मिजोरम	0	16	0	14	0	13
26	नागालैंड	0	8	0	7	0	11
27	ओडिशा	13	0	0	0	0	0
28	पुडुचेरी	0	0	0	0	0	0
29	पंजाब	76	0	37	0	25	0
30	राजस्थान	92	69	53	40	25	10
31	सिक्किम	0	2	0	1	0	4
32	तमिलनाडु	117	4	55	3	41	1
33	तेलंगाना	35	17	11	8	12	6
34	त्रिपुरा	5	11	4	5	3	6
35	उत्तर प्रदेश	234	11	115	10	178	7
36	उत्तराखंड	18	4	14	3	14	9
37	पश्चिमी बंगाल	0	0	0	0	0	0
योग		**1330**	**466**	**681**	**287**	**565**	**195**

स्रोत: न्याय विभाग का एमआईएस पोर्टल

31.12.2021 तक जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति न्यायिक अधिकारी की कार्यरत पद संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	सिविल न्यायाधीश(जूनियर डिविजन)		सिविल न्यायाधीश (सीनियर डिविजन)		जिला न्यायाधीश/डी.जे.	
		एससी	एसटी	एससी	एसटी	एससी	एसटी
1	अंदमान और निकोबार	0	0	0	0	0	0
2	आंध्र प्रदेश	42	15	23	9	19	1
3	अरुणाचल प्रदेश	0	13	0	9	0	9
4	असम	15	22	7	16	0	0
5	बिहार	115	9	64	5	38	1
6	चंडीगढ़	2	0	0	0	0	0
7	छत्तीसगढ	23	56	20	30	25	27

8	दादरा और नागर	0	0	0	0	0	0
9	दमण् और दीव	0	0	0	0	0	0
10	दिल्ली	54	6	14	2	8	1
11	गोवा	0	2	0	0	0	0
12	गुजरात	58	2	46	3	10	0
13	हरियाणा	38	0	26	0	22	0
14	हिमाचल प्रदेश	7	4	8	2	7	2
15	जम्मू -कश्मीर	7	9	5	6	8	5
16	झारखंड	26	61	0	0	0	0
17	कर्नाटक	76	11	48	8	49	9
18	केरल	21	1	9	0	7	0
19	लद्दाख	0	4	0	2	0	0
20	लक्षदीप	0	0	0	1	0	0
21	मध्य प्रदेश	104	91	69	84	60	59
22	महाराष्ट्र	140	2	43	3	44	2
23	मणिपुर	1	5	2	4	1	4
24	मेघालय	0	20	0	14	0	12
25	मिजोरम	0	16	0	13	0	13
26	नागालैंड	0	0	0	0	0	0
27	ओडिशा	17	0	0	0	0	0
28	पुडुचेरी	0	0	0	0	0	0
29	पंजाब	79	0	38	0	29	0
30	राजस्थान	87	66	37	30	43	20
31	सिक्किम	0	2	0	1	0	4
32	तमिलनाडु	121	5	58	3	46	1
33	तेलंगाना	40	22	11	7	15	7
34	त्रिपुरा	5	11	4	5	3	6
35	उत्तर प्रदेश	193	14	155	11	155	7
36	उत्तराखंड	20	4	14	3	13	9
37	पश्चिमी बंगाल	0	0	0	0	0	0
योग		**1291**	**473**	**701**	**271**	**602**	**199**

स्रोत: न्याय विभाग का एमआईएस पोर्टल

31.12.2022 तक जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में एस सी/एसटी न्यायिक अधिकारियों की कार्यरत पद संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	सिविल न्यायाधीश(जूनियर डिविजन)		सिविल न्यायाधीश (सीनियर डिविजन)		जिला न्यायाधीश/डी.जे.	
		एससी	एसटी	एससी	एसटी	एससी	एसटी
1	अंदमान और निकोबार	0	0	0	0	0	0
2	आंध्र प्रदेश	39	16	32	12	19	1
3	अरुणाचल प्रदेश	0	12	0	11	0	9
4	असम	15	22	7	16	0	0
5	बिहार	115	9	62	5	35	1
6	चंडीगढ़	3	0	0	0	1	0
7	छत्तीसगढ	27	65	19	31	27	27
8	दादरा और नागर हवेली	0	0	0	0	0	0
9	दमण और दीव	0	0	0	0	0	0
10	दिल्ली	55	6	9	1	8	1
11	गोवा	0	2	0	0	0	0
12	गुजरात	54	1	50	4	9	0
13	हरियाणा	38	0	26	0	22	0
14	हिमाचल प्रदेश	9	4	7	2	7	2
15	जम्मू - कश्मीर	9	8	6	6	7	3
16	झारखंड	20	55	0	0	0	0
17	कर्नाटक	76	15	49	7	59	9
18	केरल	16	1	13	0	7	1
19	लद्दाख	0	2	0	2	0	1
20	लक्षदीप	0	0	0	1	0	0
21	मध्य प्रदेश	125	97	59	81	74	56
22	महाराष्ट्र	140	2	43	3	44	2
23	मणिपुर	1	4	1	5	1	4
24	मेघालय	0	25	0	14	0	15
25	मिजोरम	0	16	0	10	0	15
26	नागालैंड	0	0	0	0	0	0
27	ओडिशा	17	0	0	0	0	0
28	पुडुचेरी	0	0	0	0	0	0
29	पंजाब	79	0	36	0	27	0
30	राजस्थान	65	58	46	29	47	22
31	सिक्किम	0	2	0	0	0	5
32	तमिलनाडु	120	5	57	3	43	1
33	तेलंगाना	33	18	17	11	13	7
34	त्रिपुरा	5	7	4	9	4	7
35	उत्तर प्रदेश	193	15	151	11	143	7
36	उत्तराखंड	16	3	16	4	15	8
37	पश्चिमी बंगाल	0	0	0	0	0	0
योग		**1270**	**470**	**710**	**278**	**612**	**204**

स्रोत: न्याय विभाग का एमआईएस पोर्टल

31.12.2023 तक जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति न्यायिक अधिकारी की कार्यरत पदसंख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	सिविल न्यायाधीश(जूनियर डिविजन)		सिविल न्यायाधीश (सीनियर डिविजन)		जिला न्यायाधीश/डी.जे.	
		एससी	एसटी	एससी	एसटी	एससी	एसटी
1	अंदमान और निकोबार	0	0	0	0	0	0
2	आंध्र प्रदेश	44	17	23	10	28	3
3	अरुणाचल प्रदेश	0	9	0	16	0	8
4	असम	13	15	9	18	0	0
5	बिहार	129	9	63	5	48	3
6	चंडीगढ़	3	0	0	0	1	0
7	छत्तीसगढ	26	62	13	29	28	27
8	दादरा और नागर हवेली	0	0	0	0	0	0
9	दमण और दीव	0	0	0	0	0	0
10	दिल्ली	48	21	8	0	8	1
11	गोवा	0	2	0	0	0	0
12	गुजरात	59	1	50	4	8	0
13	हरियाणा	48	0	26	0	20	0
14	हिमाचल प्रदेश	8	2	8	4	7	2
15	जम्मू - कश्मीर	9	7	6	6	5	3
16	झारखंड	15	36	0	0	0	0
17	कर्नाटक	80	16	50	7	58	9
18	केरल	18	1	12	0	9	1
19	लद्दाख	0	3	0	2	0	0
20	लक्षदीप	0	0	0	1	0	0
21	मध्य प्रदेश	131	66	78	116	72	54
22	महाराष्ट्र	140	2	43	3	44	2
23	मणिपुर	0	6	0	4	0	4
24	मेघालय	0	25	0	14	0	15
25	मिजोरम	0	16	0	10	0	15
26	नागालैंड	0	0	0	0	0	0
27	ओडिशा	26	3	0	0	0	0
28	पुडुचेरी	0	0	0	0	0	0
29	पंजाब	78	0	37	0	27	0
30	राजस्थान	80	59	50	43	53	23
31	सिक्किम	0	2	0	0	0	5
32	तमिलनाडु	119	5	57	4	39	1
33	तेलंगाना	38	20	15	7	15	13
34	त्रिपुरा	5	9	4	7	4	6
35	उत्तर प्रदेश	146	11	134	15	196	7
36	उत्तराखंड	16	3	14	4	16	5
37	पश्चिमी बंगाल	0	0	0	0	0	0
योग		**1279**	**428**	**700**	**329**	**686**	**207**

स्रोत: न्याय विभाग का एमआईएस पोर्टल

31.12.2024 तक जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति न्यायिक अधिकारियो की कार्यरत पद संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	सिविल न्यायाधीश(जूनियर डिविजन)		सिविल न्यायाधीश (सीनियर डिविजन)		जिला न्यायाधीश/डी.जे.	
		एससी	एसटी	एससी	एसटी	एससी	एसटी
1	अंदमान और निकोबार	0	0	0	0	0	0
2	आंध्र प्रदेश	53	19	23	10	30	3
3	अरुणाचल प्रदेश	0	9	0	16	0	7
4	असम	16	23	12	21	6	7
5	बिहार	129	9	63	5	48	3
6	चंडीगढ़	7	0	0	0	1	0
7	छत्तीसगढ	26	57	17	45	30	26
8	दादरा और नागर हवेली	0	0	0	0	0	0
9	दमण और दीव	0	0	0	0	0	0
10	दिल्ली	46	21	12	1	10	1
11	गोवा	0	2	0	0	0	0
12	गुजरात	59	1	50	4	8	0
13	हरियाणा	31	0	42	0	21	0
14	हिमाचल प्रदेश	8	2	8	4	6	1
15	जम्मू - कश्मीर	13	11	6	7	9	8
16	झारखंड	15	31	0	0	0	0
17	कर्नाटक	77	19	90	20	60	9
18	केरल	20	0	11	1	10	1
19	लद्दाख	1	2	0	4	0	1
20	लक्षदीप	1	0	0	1	0	0
21	मध्य प्रदेश	122	55	79	106	66	73
22	महाराष्ट्र	140	2	43	3	44	2
23	मणिपुर	0	6	0	4	0	4
24	मेघालय	0	15	0	21	0	18
25	मिजोरम	0	13	0	17	0	15
26	नागालैंड	0	0	0	0	0	0
27	ओडिशा	30	4	0	0	0	0
28	पुडुचेरी	3	0	0	0	0	0
29	पंजाब	118	0	34	0	33	0
30	राजस्थान	64	47	60	52	59	24
31	सिक्किम	0	1	0	2	0	5
32	तमिलनाडु	119	5	57	4	35	1
33	तेलंगाना	38	20	15	7	15	13
34	त्रिपुरा	5	9	4	7	4	6
35	उत्तर प्रदेश	214	17	134	15	193	7
36	उत्तराखंड	16	3	12	4	18	5
37	पश्चिमी बंगाल	0	0	0	0	0	0
कुल		**1371**	**403**	**772**	**381**	**706**	**240**

स्रोत: न्याय विभाग का एमआईएस पोर्टल

****